



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

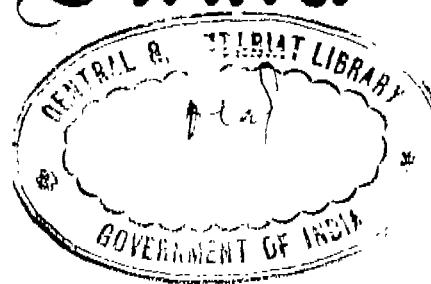
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 47 ]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 20, 2001/फाल्गुन 1, 1922

No. 47]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 20, 2001/PHALGUNA 1, 1922

वाणिज्य एवम् उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2001

**विषय :** सऊदी अरब तथा रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित हैक्सामिन के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करना।

सं. 12/1/2000-डीजीएडी.—मै. सिमालिन कैमिकल इंडस्ट्रीज लि., बड़ौदा और मै. रोकफोर्ड पैट्रो कैमिकल इंडस्ट्रीज लि., इंदौर ने सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और सीमाशुल्क टैरिफ (पारित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियम, 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक याचिका दायर की है जिसमें सऊदी अरब तथा रूस मूल के अथवा वहां से निर्यातित हैक्सामिन के पाटन का आरोप लगाया गया है तथा पाटनरोधी जांच करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

1. **शामिल उत्पाद:** वर्तमान जांच शामिल उत्पाद सऊदी अरब तथा रूस मूल का अथवा वहां से निर्यातित हैक्सामिन है।

हैक्सामिन सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के सीमाशुल्क उप शीर्ष सं. 2921.2901 के तहत वर्गीकृत है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह से वर्तमान जांच के मामले में बाध्यकर नहीं है।

**2. घरेलू उद्योग की स्थिति:** याचिकाकर्ता सहित भारत में हैक्सामिन के चार उत्पादक हैं।

कुल घरेलू उत्पादन में याचिकाकर्ताओं का हिस्सा <sup>५०.५%</sup> प्रतिशत बनता है और इसलिए वह याचिका दायर करने की मूलभूत शर्तों को पूरा करता है।

**3. शामिल देश:** वर्तमान जांच में शामिल देश सऊदी अरब और रूस हैं।

**4. समान वस्तुएं-** याचिकाकर्ता का दावा है कि उसके द्वारा उत्पादित माल सऊदी अरब तथा रूस के मूल के या वहाँ से निर्यातित माल के समान वस्तु हैं। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित माल को नियमावली के अर्थों के भीतर संबद्ध देशों से आयातित माल के समान वस्तु माना जा रहा है।

**5. पाटन और पाटन मार्जिन:**

**सामान्य मूल्य:** याचिकाकर्ताओं ने सऊदी अरब तथा रूस में सामान्य मूल्य का दावा हैक्सामिन के उत्पादन की परिकलित लागत के आधार पर किया है।

**निर्यात कीमत:** याचिकाकर्ताओं ने डी जी सी आई एंड एस तथा दूसरे स्रोतों द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत का दावा किया है। सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना करने पर पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से बहुत अधिक हैं।

इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि सऊदी अरब तथा रूस में विचाराधीन उत्पाद का सामान्य मूल्य, उस मूल्य से बहुत अधिक है जिस पर इसे भारत को निर्यात किया गया। इस बात से प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि सऊदी अरब तथा रूस के निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है।

**6. क्षति एवं कारणात्मक संबंध:** घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न आर्थिक संकेतक जैसे उत्पादन, बिक्री, लाभ/हानि इत्यादि समग्र तथा संचयी रूप से यह बताते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। इस बात के प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों से घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हुई है।

**7. पाटनरोधी जांच की शुरूआत:** उपरोक्त पैराग्राफ को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी, संबद्ध देशों के मूल की या वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं की कथित डम्पिंग होने, उसकी मात्रा तथा उसके प्रभाव की पाटन-रोधी जांच आरंभ करते हैं।

**8. जांच की अवधि:** वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 1999 से 30 सितम्बर, 2000 (18 महीने) तक की है।

**9. सूचना देना:** संबद्ध देशों में निर्यातकों और भारत में आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है कि वे अपने विचार तथा संबंधित सूचना निर्धारित रूप में तथा निर्धारित ढंग से निर्दिष्ट प्राधिकारी, भारत सरकार, वाणिज्य विभाग, पाटनरोधी शुल्क महानिदेशालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 को भेज दें। अन्य कोई हितबद्ध पार्टी भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर निर्धारित रूप में और निर्धारित ढंग से जांच से संबंधित अभिवेदन दे सकती है।

10. **समय सीमा:** वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में दी जाए जो उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर पहुंच जानी चाहिए। तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है, उन्हें अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर सूचना देनी होगी। यह नोट किया जाए कि अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने के लिए उपरोक्त समयावधि को बढ़ाए जाने के बारे में कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

11. पाटनरोधी जांच चूंकि एक समयबद्ध कार्रवाई है, इसलिए यदि निर्धारित समय के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त हुई सूचना अधूरी है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपरोक्त नियमों के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है।

12. **सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण:** नियम 6(7) के अनुसार रुचि रखने वाली कोई भी पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं।

13. यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं करती है या महत्वपूर्ण ढंग से जांच में बाधा डालती है तो प्राधिकारी, अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है तथा केन्द्रीय सरकार को यथोजित सिफारिशें कर सकता है।

एल. बी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

#### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

#### INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2001

**Subject :** Initiation of anti-dumping investigations concerning import of Hexamine originating in or exported from Saudi Arabia and Russia.

**No. 12/1/2000-DGAD.**—M/s. Simalin Chemical Industries Ltd., Baroda and M/s. Rockford Petro Chemical Industries Ltd., Indore have filed a petition before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 alleging dumping of Hexamine originating in or exported from Saudi Arabia and Russia and have requested for initiation of anti-dumping investigations and levy of anti-dumping duties.

**1. Product Involved:** The product under investigation in the present case is Hexamine originating in or exported from Saudi Arabia and Russia.

Hexamine is classified under Customs sub-heading no. 2921.2901 of the Customs Tariff Act, 1975. The classification is however indicative only and in no way binding on the scope of the present investigations.

2. **Domestic Industry Standing:** There are four producers of Hexamine in India including the petitioners.

The petitioners accounts for 60.4% of the total domestic production and therefore satisfies the standing to file the present petition.

3. **Country(ies) Involved:** The countries involved in the present investigations are Saudi Arabia and Russia.

4. **Like Goods:** The petitioner has claimed that goods produced by it are like articles to the goods originating in or exported from Saudi Arabia and Russia. Goods produced by the petitioner are being treated as Like Articles to the goods imported from the subject countries within the meaning of the Rules.

5. **Dumping and Dumping Margin:**

**Normal Value:** The petitioners have claimed normal value in Saudi Arabia and Russia on the basis of constructed cost of production of Hexamine.

**Export price:** The petitioners have claimed export price based on the data published by DGCIS and secondary sources. Comparing the normal value and export price the dumping margins are significantly higher than the de-minimis limit.

There is sufficient evidence that the normal values of the product under consideration in Saudi Arabia and Russia are significantly higher than the prices at which it has been exported to India, indicating, *prima facie*, that the subject goods are being dumped by the exporters from Saudi Arabia and Russia.

6. **Injury and Causal Link:** The various economic indicators relating to domestic industry such as production, sales, profit/loss etc. collectively and cumulatively, indicates that the domestic industry has suffered injury. There is sufficient *prima facie* evidence that the imports of the product under consideration have caused material injury to the domestic industry.

7. **Initiation of Anti-Dumping Investigation:** In view of the foregoing paragraph, the Designated Authority initiates anti-dumping investigations to determine the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

8. **Period of Investigation:** The period of investigation for the purpose of the present investigations is 1<sup>st</sup> April, 1999 to 30<sup>th</sup> September 2000 (18 months).

9. **Submission of Information:** The exporters in the subject countries and the importers in India known to be concerned are being addressed separately to submit relevant information in

the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority, Ministry of Commerce, Directorate General of Anti-Dumping, Udyog Bhavan, New-Delhi – 110011. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

10. **Time Limit:** Any information relating to the present investigations should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are, however, required to submit the information within forty days from the date of letter addressed to them separately. It may kindly be noted that no requests whatsoever shall be entertained for extension of the above-stated time limit for submission of the required information.

11. Anti-dumping investigations being a time bound exercise, the Designated Authority may record its findings on the basis of facts available on record in accordance with the Rules supra, if no response is received within the time stipulated or the information is incomplete in any respect.

12. **Inspection of Public File:** In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

13. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority

